

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3359
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

सीमांचल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति

3359. श्री तारिक अनवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सीमांचल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है जहां हाल ही में प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण व्यापक व्यवधान की खबरें सामने आई हैं;

(ख) विगत तीन महीनों के दौरान इस विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में आंकड़े क्या हैं और प्रभावित घरों की संख्या कितनी है तथा उक्त क्षेत्र में पुनरुद्धार हेतु की गई कार्रवाई क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास राज्य एसेंसियों के समन्वय से इस क्षेत्र के लिए ग्रिड सुदृढीकरण, दुर्गम क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) की तैनाती जैसे दीर्घकालिक उपायों को लागू करने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 520.511 गीगावाट है। भारत ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है और देश को विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता में बदल दिया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में बिहार राज्य के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण अनुबंध-1 पर है। ऊर्जा आपूर्ति और ऊर्जा आवश्यकता के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2.0% से घटकर वर्तमान वर्ष के दौरान लगभग 'शून्य' हो गया है। इसलिए, बिहार राज्य के लिए ऊर्जा आपूर्ति ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता कर रही है।

राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) से प्राप्त विवरण के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसंबर, 2025 तक) में बिहार राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे क्रमशः 22.9 घंटे और 23.4 घंटे हैं।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र यूटिलिटी को छोड़कर) को हानि न्यूनीकरण वाले अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें से वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 10,559 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2,021 करोड़ रुपये की राशि बिहार राज्य के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रिड सुदृढीकरण सहित देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार राज्य के लिए जिलावार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में बिहार राज्य के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	39,545	38,762	783	2.0
2023-24	41,514	40,918	596	1.4
2024-25	44,393	44,217	176	0.4
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	40,749	40,735	14	0.0

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यो का जिला वार विवरण

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्य (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य (करोड़ रुपये)
1	अररिया	204	45
2	बेगूसराय	235	57
3	दरभंगा	277	71
4	गोपालगंज	152	43
5	कटिहार	231	42
6	खगड़िया	175	26
7	किशनगंज	178	36
8	मधुपुरा	124	25
9	मधुबनी	240	44
10	मुजफ्फरपुर	252	29
11	पश्चिम चंपारण	400	63
12	पूर्वी चंपारण	260	73
13	पूर्णिया	257	56
14	सहरसा	125	33
15	समस्तीपुर	286	61
16	सारण	182	57
17	शिवहर	66	7
18	सीतामढ़ी	161	42
19	सिवान	185	54
20	सुपौल	285	38
21	वैशाली	308	61
22	अरवल	105	9
23	औरंगाबाद	214	44
24	बांका	164	25
25	भागलपुर	243	26
26	भोजपुर	329	57
27	बक्सर	258	33
28	गया	453	37
29	जमुई	182	25
30	जहानाबाद	114	24
31	कैमूर	282	33
32	लखीसराय	124	24
33	मुंगेर	170	42
34	नालंदा	346	80
35	नवादा	256	40
36	पटना	1,751	466
37	रोहतास	304	66
38	शेखपुरा	125	18
	कुल योग	10,003	2,013
	आईटी/ओटी कार्य	400	0
	पीएमए लागत	156	8
	कुल	10,559	2,021